रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3388] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 2019/आश्विन 25, 1941
No. 3388] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2019/ASVINA 25, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3726 (अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए ;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 अप्रैल, 2019 से भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1614(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 18 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छह मास की अवधि के लिए अंतिम बार लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया है ;

और केंद्रीय सरकार का यह मत है कि लोक हित उक्त उद्योग की लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति की छह मास की और अवधि के लिए विस्तार करने की अपेक्षा करता है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाएं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 21 अक्तूबर, 2019 से लोक उपयोगिता सेवा होंगी ।

[फा. सं. एस.-11017/5/97-आईआर(पीएल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2019

S.O. 3726(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Banking industry, which is covered under item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 18th April, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1614(E), dated the 18th April, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 18th April, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Banking industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 21st October, 2019**.**

[F. No. S-11017 / 5 / 97- IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.18 12:58:46 +05'30'